नॉट बाइ एमएसपी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि) से संबंधित है।

14 सितम्बर, 2018

इंडियन एक्सप्रेस

''अगर किसानों को लाभकारी दरों का भुगतान करना ही है, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका विकृत होने के माध्यम से नहीं बल्कि बाजारों तक पहुँच को आसान बना कर किया जा सकता है।''

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को अपने अनुमानित उत्पादन लागत में कम से कम 1.5 गुना कवर करने के उद्देश्य से की गयी तेजी से बढ़ोतरी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब निर्णय को लागू करने के लिए नए तरीके ढूंढ रही है।

देखा जाये तों खरीफ फसलों के लिए मार्केटिंग का सीजन शुरू होने ही वाला है, लेकिन यह एक अशुभ संकेत है कि ज्यादातर फसलें - मूंग, उरद और मूंगफली से बाजरा और ज्वार आदि - मंडी के अपने शीर्ष स्तर तक पहुँचने से पहले एमएसपी के नीचे बेचे जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा उठाये गए कदम से निजी व्यापारियों को एमएसपी पर खरीददारी करने पर मजबूर किया जा रहा है और ऐसा ना करने पर उन्हें एक साल की जेल दी जा रही है। अब, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-आशा अर्थात प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान नामक एक नई पहल को मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान मूल रूप से तीन योजनाओं को जोड़ती है - एक मौजूदा (मूल्य समर्थन योजना, जिसमें दाल और तिलहन की एमएसपी आधारित खरीद नाफेड जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जाती है), इसे मध्यप्रदेश और हरियाणा ने सीमित सफलता के साथ प्रयास किया (मूल्य कमी भुगतान योजना) और एक नया (निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना, जिसमें निजी खिलाड़ियों को भी एमएसपी संचालन के लिए सूचीबद्ध किया गया है)।

नई नीति में राज्य सरकारों को विकल्प होगा कि वे कीमतें एमएसपी से नीचे जाने पर वे किसानों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकें।

योजना के बारे में विस्तार से समझें तो - मौजूदा मूल्य सहायता योजना के तहत दलहन तिलहन और कोपरा समेत तमाम फसलों की सीधी खरीद केंद्र की एजेंसियों के साथ ही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

इसमें खरीद खर्च की भरपाई केंद्र सरकार करेगी और साथ ही केंद्र सरकार खरीद में हुए नुकसान का 25 फीसदी भी वहन करेगी। मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना के तहत वो सभी तिहलन फसलें शामिल होंगी जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का एलान हो चुका है ।

हालांकि पीएम-आशा या नए 1.5 गुणा लागत वाले एमएसपी फॉर्मूला के पीछे नेक इरादे पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन यहाँ सवाल फिर से इसके कार्यान्वयन के संबंध में ही है।

जब आज बाजार की कीमतें लगातार एमएसपी के नीचे हैं, तो इसका मतलब केवल यह हुआ कि उत्तरार्द्ध आपूर्ति मांग बुनियादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऐसा होने पर, एमएसपी पर खरीद करने और दोनों बिक्री के साथ-साथ भंडारण हानि की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकारी एजेंसियों पर होगी।

अब सवाल यह उठता है कि ये एजेंसियां कितनी खरीद और स्टोर कर सकती हैं? इसके अलावा, वे इन शेयरों का निपटान कैसे करेंगे? नाफेड अब 2017-18 में खरीदे गए लगभग 6.5 मिलियन टन दालों और तिलहनों के साथ संघर्ष कर रहा है और वर्तमान में एमएसपी के नीचे बाजार में वापस आ गया है।

यहाँ तक कि यदि निजी निगमों को सरकार की ओर से खरीद के साथ सौंपा गया है, तो उन्हें नुकसान के लिए मुआवजा देना होगा और एमएसपी पर केवल 15 प्रतिशत तक सेवा शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसीलिए सवाल यह भी उठता है कि मोदी सरकार अगले एक महीने में पीएम-आशा के तहत इन सभी खरीद तंत्र को स्थापित करने की योजना कैसे बना रही है?

अगर किसानों को लाभकारी दरों का भुगतान करना है, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका विकृत होने के माध्यम से नहीं बल्कि बाजारों को आसान बना कर किया जा सकता है।

किसानों को बाजार संकेतों के आधार पर किसी भी फसल का उत्पादन करने की छूट दी जाए और वर्तमान समय में चल रहे किसी भी मूल्य पर बेचने वाले व्यापारियों को भुगतान करने की छूट दी जानी चाहिए।

साथ ही, सभी भंडारण प्रतिबंधों को दूर करते हुए भारत के भीतर किसी भी मंडी से कहीं भी खरीदने की अनुमति देकर प्रतिस्पर्धा शुरू की जानी चाहिए। वास्तव में कृषि उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बाजार, फसल उगाए जाने से स्वतंत्र एक फ्लैट प्रति एकड़ सरकारी भुगतान के साथ, समय की आवश्यकता है।

* * *

पीएम- आशा योजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan-PM-AASHA) को मंजूरी दे दी है।
- यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक असाधारण कदम है जिससे किसानों के कल्याण हेतु किये जाने वाले कार्यों में अत्यधिक सफलता मिलने की आशा है।

उद्देश्य-

- इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिये उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में डेढ़ गुना वृद्धि करने के बाद खरीफ सीजन की खरीद शुरू होने से ठीक पहले उपज की खरीद को सुनिश्चित किया गया है।

प्रमुख घटक

- नई समग्र योजना में किसानों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने की व्यवस्था शामिल है और इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं :-
- मूल्य समर्थन योजना (PSS)
- मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना (PDPS)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना (PPSS)

मूल्य समर्थन योजना

- इसके तहत दालों, तिलहन और गरी की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी।
- यह भी निर्णय लिया गया है कि नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (FCI) भी राज्यों/जिलों में PSS परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।
- खरीद पर होने वाले व्यय और खरीद के दौरान होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार मानकों के मुताबिक वहन करेगी।

मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना

- इसके तहत उन सभी तिलहनी फसलों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिये एमएसपी को अधिसूचित कर दिया जाता है।
- इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान पहले से ही पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिये अधिसूचित बाजार में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।
- समस्त भुगतान सीधे किसान के पंजीकृत बैंक खाते में किया जाएगा।
- इस योजना के तहत फसलों की कोई भौतिक खरीदारी नहीं की जाती है क्योंकि अधिसूचित बाजार में बिक्री करने पर एमएसपी और बिक्री/औसत मूल्य में अंतर का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है।
- PDPS के लिये केंद्र सरकार द्वारा सहायता, तय मानकों के अनुसार दी जायेगी।

निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना

- तिलहन के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चुनिंदा जिला/जिले की APMC में प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना शुरू कर सकते हैं जिसमें निजी स्टॉकिस्टों की भागीदारी होगी।
- प्रायोगिक आधार पर चयनित जिला/जिले की चयनित APMC तिलहन की ऐसी एक अथवा उससे अधिक फसलों को कवर करेगी जिसके लिये MSP को अधिसूचित किया जा चुका है।
- चूँकि यह योजना अधिसूचित जिंस की भौतिक खरीदारी की दृष्टि से चै से काफी मिलती-जुलती है, इसलिये यह प्रायोगिक आधार पर चयनित जिलों में PSS/PDPS को प्रतिस्थापित करेगी।

व्यय

- कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है जिससे यह यह गारंटी बढ़कर 45,550 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुँच गई है।
- इसके अलावा, खरीद परिचालन के लिये बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के क्रियान्वयन के लिये 15,053 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से कौन-सा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के संबंध में सत्य है?
   (a) यह ऐसा मूल्य है, जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को सरकार खरीदने के लिए तैयार रहती है।
   (b) इसकी घोषणा वर्ष में दो बार रबी एवं खरीफ के मौसम में की जाती है।
   (c) इसकी सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा की जाती है।
   (d) उपर्युक्त सभी

2. हाल ही में चर्चित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में निम्नलिखित में से कौन-से घटक शामिल हैं?
   1. मूल्य समर्थन योजना
   2. मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना
   3. निजी खरीद एवं स्टाकिस्ट योजना

   कूट-
   (a) 1 और 2
   (b) 2 और 3
   (c) 1 और 3
   (d) 1, 2 और 3

3. मूल्य सहायता योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन और कोपरा सहित कई फसलों की खरीद केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही सरकार द्वारा की जायेगी।
   2. इस योजना के अंतर्गत खरीद मूल्य की पूर्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों
   (d) न तो 1 न ही 2

1. **Which of the following is correct regarding Minimum Support Price (MSP)?**
   (a) It is the price at which government is ready to procure grains sold by farmers.
   (b) It is notified two times in a year in Rabi and Kharif seasons.
   (c) It is recommended by Commission for Agricultural costs and Prices.
   (d) All of the above

2. **Which of the following factors are included in the recently in discussion Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan?**
   1. Price Support Scheme
   2. Price Deficiency Payment Scheme
   3. Private Procurement and Stockist Scheme

   Code-
   (a) 1 and 2
   (b) 2 and 3
   (c) 1 and 3
   (d) 1, 2 and 3

3. **Consider the following statements regarding Price Support Scheme-**
   1. Under this, many crops along with Pulses, oilseeds and Kopara will be purchased by central agencies with State Governments.
   2. Under this scheme, the procurement price will be compensated by Central Government.

   Which of the above statements is/are not correct?
   (a) Only 1
   (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2
   (d) Neither 1 nor 2

नोट :
13 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(d), 3(d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. ''सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के बजाए किसानों की बाजार तक पहुँच को आसान बनाकर उनके लागत को लाभकारी बनाया जा सकता है।'' अपना मत प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

Instead of providing minimum support price by government, by easing the reach of farmers to the market, their spending can be made profitable. Give your opinion. (250 Words)